



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 मार्च, 2006/7 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 28 मार्च, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-बजट/1-18/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2006

को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनाथ मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/—

(जे. आर. गाज़टा)

सचिव ।

2006 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 93,31,00,15,000 (तिरानवें अरब, ईकतीस करोड़ पन्द्रह हजार रुपये) हैं संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2006-2007 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए 93,31,00,15,000 रुपये की राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
भाग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा (राजस्व) (पूँजी)	7,65,21,000 60,01,000	22,07,000 —	7,87,28,000 60,01,000
2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् (राजस्व) (पूँजी)	3,98,25,000 —	1,80,93,000 —	5,79,18,000 —
3	न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूँजी)	33,94,89,000 16,06,27,000	7,53,28,000 —	41,48,17,000 16,06,27,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूँजी)	49,71,25,000 5,00,000	2,47,37,000 —	52,18,62,000 5,00,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) (पूँजी)	2,13,33,30,000 1,000	— —	2,13,33,30,000 1,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व) (पूँजी)	18,42,56,000 —	— —	18,42,56,000 —
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूँजी)	2,19,11,30,000 11,87,80,000	— —	2,19,11,30,000 11,87,80,000
8	शिक्षा (राजस्व) (पूँजी)	11,81,14,45,000 27,50,00,000	— —	11,81,14,45,000 27,50,00,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व) (पूँजी)	3,27,47,41,000 37,63,90,000	— —	3,27,47,41,000 37,63,90,000
10	लोक निर्माण—सड़कें, पुल तथा भवन । (राजस्व) (पूँजी)	7,55,07,12,000 1,78,58,01,000	— 1,80,00,000	7,55,07,12,000 1,80,38,01,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
11	कृषि (राजस्व)	78,28,34,000	—	78,28,34,000
	(पूँजी)	19,50,01,000	—	19,50,01,000
12	उद्यान (राजस्व)	52,66,24,000	—	52,66,24,000
	(पूँजी)	2,35,19,000	—	2,35,19,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व)	5,58,38,09,000	—	5,58,38,09,000
	(पूँजी)	3,50,00,37,000	—	3,50,00,37,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास (राजस्व)	75,34,29,000	—	75,34,29,000
	एवं मत्स्य । (पूँजी)	3,20,65,000	—	3,20,65,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व)	95,28,23,000	—	95,28,23,000
	उप-योजना । (पूँजी)	23,92,19,000	—	23,92,19,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	2,20,39,73,000	—	2,20,39,73,000
	(पूँजी)	2,36,01,000	—	2,36,01,000
17	निर्वाचन (राजस्व)	4,22,58,000	—	4,22,58,000
	(पूँजी)	—	—	—
18	उद्योग, खनिज और आपूर्ति (राजस्व)	30,46,00,000	—	30,46,00,000
	(पूँजी)	24,17,00,000	—	24,17,00,000
19	सामाजिक न्याय और (राजस्व)	1,82,37,69,000	—	1,82,37,69,000
	अधिकारिता । (पूँजी)	11,07,02,000	—	11,07,02,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	1,32,88,25,000	—	1,32,88,25,000
	(पूँजी)	5,80,96,000	—	5,80,96,000
21	सहकारिता (राजस्व)	11,61,68,000	—	11,61,68,000
	(पूँजी)	45,13,000	—	45,13,000
22	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	12,38,03,000	—	12,38,03,000
	(पूँजी)	2,77,000	—	2,77,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
23	विद्युत विकास (राजस्व) (पूंजी)	1,45,46,17,000		1,45,46,17,000
24	गृहण और लेखन सामग्री (राजस्व) (पूंजी)	9,81,68,000 20,00,000		9,81,68,000 20,00,000
25	सड़क और जल परियोजना (राजस्व) (पूंजी)	53,92,11,000 14,00,00,000		53,92,11,000 14,00,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) (पूंजी)	6,11,94,000 2,30,00,000	—	6,11,94,000 2,30,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) (पूंजी)	26,59,62,000 13,22,00,000	—	26,59,62,000 13,22,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं गांव योजना तथा आवागमन (राजस्व) (पूंजी)	40,72,80,000 50,35,00,000	—	40,72,80,000 50,35,00,000
29	वित्त (राजस्व) (पूंजी)	7,17,99,63,000 10,96,01,000	17,53,56,26,000 11,40,18,55,000	24,71,55,89,000 11,51,14,56,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) (पूंजी)	23,00,41,000 8,11,49,000	—	23,00,41,000 8,11,49,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व) (पूंजी)	2,58,89,47,000 62,37,95,000	—	2,58,89,47,000 62,37,95,000
	जोड़ (राजस्व)	55,46,70,94,000	17,65,59,91,000	73,12,30,85,000
	(पूंजी)	8,76,70,75,000	11,41,98,55,000	20,18,69,30,000
	कुल (जोड़)	64,23,41,69,000	29,07,58,46,000	93,31,00,15,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत को संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की सैनिक निधि में से वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में सैनिक निधि पर प्रस्तावित व्ययों और विधान सभा द्वारा विलयन अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के वित्तियोजन का सम्बन्ध करने के लिए पुर स्थापित है ।

मीरअनम सिंघ,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला
तारीख 28 मार्च, 2006

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या फिन ए-सी (1) 1/2006)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2006 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करने हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2006.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2006

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2006-2007.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2006.

Issue of a sum of Rs. 93,31,00,15,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 93,31,00,15,000 (Ninety three hundred thirty one crores, fifteen thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2006-2007 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 De- mand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consoli- dated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue) (Capital)	7,65,21,000 60,01,000	22,07,000	7,87,28,000 60,01,000
2	Governor and Council of Ministers. (Revenue) (Capital)	3,98,25,000	1,80,93,000	5,79,18,000
3	Administration of Justice (Revenue) (Capital)	33,94,89,000 16,06,27,000	7,53,28,000	41,48,17,000 16,06,27,000
4	General Administration (Revenue) (Capital)	49,71,25,000 5,00,000	2,47,37,000	52,18,62,000 5,00,000
5	Land Revenue and District Administration. (Revenue) (Capital)	2,13,33,30,000 1,000		2,13,33,30,000 1,000
6	Excise and Taxation (Revenue) (Capital)	18,42,56,000 —	— —	18,42,56,000 —
7	Police and Allied Organisations. (Revenue) (Capital)	2,19,11,30,000 11,87,80,000	— —	2,19,11,30,000 11,87,80,000
8	Education (Revenue) (Capital)	11,81,14,45,000 27,50,00,000	— —	11,81,14,45,000 27,50,00,000
9	Health and Family Welfare. (Revenue) (Capital)	3,27,47,41,000 37,63,90,000	— —	3,27,47,41,000 37,63,90,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings. (Revenue) (Capital)	7,55,07,12,000 1,78,58,01,000	— 1,80,00,000	7,55,07,12,000 1,80,58,01,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
11	Agriculture (Revenue) (Capital)	78,28,34,000 19,50,01,000	— —	78,28,34,000 19,50,01,000
12	Horticulture (Revenue)* (Capital)	52,66,24,000 2,35,19,000	— —	52,66,24,000 2,35,19,000
13	Irrigation, Water (Revenue) Supply and Sanitation. (Capital)	5,58,38,09,000 3,50,00,37,000	— —	5,58,38,09,000 3,50,00,37,000
14	Animal Husbandry, (Revenue) Dairy Development (Capital) and Fisheries	75,34,29,000 3,20,65,000	— —	75,34,29,000 3,20,65,000
15	Planning and Backward (Revenue) Area Sub-Plan. (Capital)	95,28,23,000 23,92,19,000	— —	95,28,23,000 23,92,19,000
16	Forest and Wild Life (Revenue) (Capital)	2,20,39,73,000 2,36,01,000	— —	2,20,39,73,000 2,36,01,000
17	Election (Revenue) (Capital)	4,22,58,000 —	— —	4,22,58,000 —
18	Industries, Minerals (Revenue) and Supplies. (Capital)	30,46,00,000 24,17,00,000	— —	30,46,00,000 24,17,00,000
19	Social Justice and (Revenue) Empowerment. (Capital)	1,82,37,69,000 11,07,02,000	— —	1,82,37,69,000 11,07,02,000
20	Rural Development (Revenue) (Capital)	1,32,88,25,000 5,80,96,000	— —	1,32,88,25,000 5,80,96,000
21	Co-operation (Revenue) (Capital)	11,61,68,000 45,13,000	— —	11,61,68,000 45,13,000
22	Food and Civil Supplies (Revenue) (Capital)	12,38,03,000 2,77,000	— —	12,38,03,000 2,77,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
23	Power Development (Revenue) (Capital)	1,45,46,37,000 —	— —	1,45,46,37,000
24	Printing and Stationery (Revenue) (Capital)	9,83,68,000 20,00,000	— —	9,83,68,000 20,00,000
25	Road and Water Transport. (Revenue) (Capital)	53,92,13,000 14,00,00,000	— —	53,92,13,000 14,00,00,000
26	Tourism and Civil Aviation. (Revenue) (Capital)	6,11,94,000 2,30,00,000	— —	6,11,94,000 2,30,00,000
27	Labour, Employment and Training. (Revenue) (Capital)	26,59,62,000 13,22,00,000	— —	26,59,62,000 13,22,00,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing. (Revenue) (Capital)	40,72,80,000 50,35,00,000	— —	40,72,80,000 50,35,00,000
29	Finance (Revenue) (Capital)	7,17,99,63,000 10,96,01,000	17,53,56,26,000 11,40,18,55,000	24,71,55,89,000 11,51,14,56,000
30	Miscellaneous General Services. (Revenue) (Capital)	23,00,41,000 8,11,49,000	— —	23,00,41,000 8,11,49,000
31	Tribal Development (Revenue) (Capital)	2,58,89,47,000 62,37,95,000	— —	2,58,89,47,000 62,37,95,000
	Total (Revenue)	55,46,70,94,000	17,65,59,91,000	73,12,30,85,000
	(Capital)	8,76,70,75,000	11,41,98,55,000	20,18,69,30,000
	Grand Total	64,23,41,69,000	29,07,58,46,000	93,31,00,15,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the year 2006-2007.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 28th March, 2006.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (1) 1/2006]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2006, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 मार्च, 2006/7 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 2005

संख्या टी० सी० पी०-एफ० (5)-8/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन तैयार किए गए जिला बिलासपुर के लिए बिलासपुर योजना क्षेत्र की विकास योजना का बिना किसी उपांतरण के अनुमोदित कर दिया है।